हिमाचल प्रदेश विधान सभा

02.00 बजे अपराह्न

(राष्ट्रगान गाया गया)

महामहीम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के पंचम तथा वर्ष 2019 के प्रथम सत्र के शुभारम्भ पर मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्यों तथा आपके माध्यम से, हिमाचल प्रदेश की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह नववर्ष हम सभी को प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए शक्ति तथा प्रतिबद्धता प्रदान करेगा।

2. गत वर्ष मेरी सरकार के गठन पर प्रदेश को मुख्य मंत्री के रूप में युवा नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस नेतृत्व ने नई ऊर्जा एवं दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आरम्भ किया। प्रदेश के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जा कर लोगों से सीधे सम्पर्क किया एवं उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से निवारण किया।

3. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र को आधार बनाते हुए, गत एक वर्ष में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया है। यह गौरव का विषय है कि मेरी सरकार ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' के आदर्श को अपनाते हुए अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही अधिकतर चुनावी वायदों को प्रभावी ढंग से पूरा किया है। इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की उपलब्धियों का उल्लेख इस प्रकार से है।

4. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018–19 के लिए सभी अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत

का कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ा दिया है। सरकार की इस पहल से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिली है। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने प्रदेश में खेती को एक नई दिशा प्रदान की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य में एक नई योजना 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान' शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 9 हज़ार किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक लगभग 3 हजार कृषकों द्वारा इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

5. मिट्टी के पोषक तत्वों का सही और सन्तुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के अन्तर्गत सभी कृषकों को ऑनलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 में 4 लाख 80 हजार ऐसे कार्ड बनाए गए हैं। किसानों की फसलों को बंदरों, जंगली जानवरों एवं बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' के अन्तर्गत सौर बाड़ पर अनुदान बढ़ाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक किसानों को 22 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में 1 लाख 25 हजार कृषकों को 'प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

6. हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बागवानी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2018–19 में लगभग 2 हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत लाया गया है। राज्य में बागवानी के समग्र विकास में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन', 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' तथा 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चालू वित्त वर्ष में इन योजनाओं के अन्तर्गत उच्च मूल्य के फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए 35 हजार 500 वर्ग मीटर क्षेत्र पॉलीहाउस व ग्रीनहाउस, 5 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र छायादार जाली गृह तथा 2 हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्र प्लास्टिक–टनल के अन्तर्गत लाया गया है।

7. मेरी सरकार ने पुष्प खेती के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चालू वित्त वर्ष में 'हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना' आरम्भ की है। इस योजना में 25 हजार 268 वर्ग मीटर क्षेत्र पॉलीहाउस के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसी प्रकार, मेरी सरकार ने 'मुख्य मन्त्री मधु विकास योजना' भी आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत मौन पालकों को मौन वंश, मौन गृहों एवं मौन उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

8. बागवानी के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत 1 लाख 62 हज़ार बागवानों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 95

लाख 86 हज़ार बीमित फल पौधों पर प्रदेश सरकार द्वारा 18 करोड़ 86 लाख रूपये की राशि प्रीमियम अनुदान के रूप में वहन की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों एवं बागवानों को लागत कम करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत सेब, अन्य फलों एवं सब्जियों को कर मुक्त कर दिया है। जून, 2018 से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में फूलों की ढुलाई की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की गई है।

9 किसानों की आर्थिकी के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार ने सहकारिता के अन्तर्गत की जा रही गतिविधियों को भी नई दिशा प्रदान की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 163 करोड़ रूपये लागत की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं सोलन व मण्डी जिलों में शुरू की गई हैं जिससे इन जिलों में सहकारी आन्दोलन सुदृढ़ होगा।

10. किसानों की आर्थिकी में पशुधन का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रदेश में 8 पशु औषधालयों को स्तरोन्नत करके पशु चिकित्सालय बनाया गया और 2 नए पशु औषधालय भी खोले गए। अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग के किसानों द्वारा पाली जा रही देसी नस्ल की गायों को गर्भावस्था के दौरान 50 प्रतिशत उपदान पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए 4 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 'दुग्ध उद्यमी विकास योजना' के लाभार्थियों को देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 20 प्रतिशत व अन्य नस्लों की गाय खरीदने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त उपदान प्रदान किया जा रहा है।

11. मेरी सरकार ने प्रदेश में 'गौसेवा आयोग' गठित करने के लिए शीतकालीन विधान सभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 पारित कर दिया है। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गाय के संरक्षण, कल्याण और इनकी स्वदेशी नस्लों के संवर्धन के लिए नीतियां व कार्य योजना तैयार करना होगा। प्रदेश में बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए गौ–अभ्यारण्यों व जिला स्तरीय बड़े गौसदनों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने गौसदनों एवं गौशालाओं की वित्तीय सहायता के लिए मन्दिर न्यासों की कुल आय का 15 प्रतिशत भाग देने का महत्वपूर्ण निणर्य लिया है।

12. किसानों की आर्थिकी सुधारने हेतु मेरी सरकार द्वारा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना' के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में जल संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना, मज़दूरी एवं सामग्री के 60:40 के अनुपात को जिला स्तर पर आंकना, 100 दिनों के कार्य दिवस को 120 करना व प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही 10 प्रतिशत हिस्सेदारी को पहले ही जारी करना आदि शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक 660 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष, अब तक 4 लाख 93 हज़ार 148 परिवारों ने 220 लाख कार्य दिवस अर्जित किए हैं, जिसके

अन्तर्गत 33 हजार 757 परिवारों ने 120 दिन के कार्य दिवस पूर्ण कर लिए हैं। इस योजना के अन्तर्गत अर्जित कार्य दिवस में से 63 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए हैं।

13. चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत 15 हज़ार 873 भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्य किए गए जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 10 हज़ार टैंकों का निर्माण किया गया है, जिनकी क्षमता 8 करोड़ लीटर है। किसानों के कृषि उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत लगभग 308 किलोमीटर ग्रामीण रास्तों का निर्माण हुआ है।

14. वर्ष 2018–19 में 2 हज़ार 691 सक्रिय जलाशय मछुआरों को दो माह बन्द सीजन के दौरान दी जाने वाली सहायता को 1 हज़ार 800 रूपये से बढ़ाकर 3 हज़ार रूपये किया गया है। किसानों को आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए मेरी सरकार द्वारा 'नील क्रान्ति योजना' के अन्तर्गत 2 करोड़ 28 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करके 100 नई ट्राऊट इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है।

15. मेरी सरकार ने जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'जनमंच' आरम्भ किया है। जनवरी, 2019 तक 63 विधान सभा क्षेत्रों में 96 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 24 हज़ार 424 मांगपत्र एवं शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल जनता की समस्याओं का निपटारा किया गया है बल्कि 246 स्वास्थ्य कैम्प भी लगाए गए, जिनमें 38 हज़ार 178 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 हज़ार 578 इंतकाल निपटाए गए, 743 योजनाओं का निरीक्षण किया गया, 28 हज़ार 225 विभिन्न प्रमाण–पत्र जारी किए गए, 19 हज़ार 300 लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कागज़ात पूर्ण करवाए गए, 436 ग्राम पंचायतों तथा 121 अन्य स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख 74 हज़ार डिजिटल राशन कार्ड जारी किए गए व 1 लाख 42 हज़ार लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए।

16. मेरी सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा अनेक प्रणालियों को लागू किया जिसमें समग्र समाधान, हिम प्रगति, जनमंच, रोज़गार सृजन, सहकारिता के ऑनलाईन आवेदन, प्रदेश व सभी ज़िलों की वेबसाइट का देश भर में सबसे पहले नवीनीकरण उल्लेखनीय हैं। मानव सम्पदा, ई–विधान व मिड–डे मील के सॉफ्टवेयर का देश के अन्य राज्यों में भी अनुकरण किया गया जोकि प्रशंसनीय है। हिमाचल प्रदेश देश भर में अपने नागरिकों को 'ई–बजट', 'एमहिमभूमि', 'सर्किल रेट्स', 'शक्ति महिला सुरक्षा' व 'शोर नहीं' जैसी मोबाईल ऐप्पस सुविधाएं प्रदान करने

वाला अग्रणी राज्य बना है। यह इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि चालू वित्त वर्ष में मानव सम्पदा व ई–विधान को राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस और वेब–पोर्टल को वेब–रत्न पुरस्कार से प्रदेश को सम्मानित किया गया है।

17. सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के लोगों के साथ जुड़ने के लिए, मेरी सरकार ने मुख्य मंत्री आई0टी0 प्रकोष्ठ की स्थापना की है। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता एवं जवाबदेही बढ़ाने और पेपर रहित वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2018 में 19 कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रारम्भ किया गया है जिसके माध्यम से 6 हजार 953 फाइलें ऑनलाईन चल रही है। प्रदेश के 6 विकास खण्डों की 221 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है।

18. मेरी सरकार द्वारा 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना' के तहत 3 हज़ार 175 करोड़ रूपये 56 योजनाओं के लाभार्थियों के आधार–सक्षम बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तान्तरित किए गए हैं।

19. मेरी सरकार द्वारा 'एकल खिड़की प्रणाली' के अंतर्गत निवेशकों की सुविधा के लिए एक 'सिंगल प्वाइंट कॉन्टैक्ट' की सुविधा विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत 10 संबंधित विभागों की 37 सेवाओं को जोड़ा गया है। अब निवेशक ऑनलाईन सांझा आवेदन पत्र द्वारा बिना किसी दखल के अपनी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों की स्वीकृतियां प्राप्त कर सकते हैं।

20. मेरी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और लेखों के सही रख–रखाव के लिए 'प्रिया सॉफ्ट' सॉफ्टवेयर में सभी पंचायतों के खातों का रख–रखाव किया जा रहा है। प्रथम अप्रैल, 2018 से परिवार रजिस्टर ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

21. मेरी सरकार द्वारा 'डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के अन्तर्गत जिला कांगड़ा, बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, हमीरपुर, लाहौल–स्पीति व मण्डी की मुसाबियों के डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब इन्हें जमाबंदियों के साथ एकीकृत करके राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आम जनता अपने जमाबंदी के डाटा को मुसाबियों सहित डाउनलोड कर सकती है।

22. कुल्लू, चम्बा और लाहौल–स्पीति जिलों में 23 और 24 सितम्बर, 2018 को भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण कई पर्यटक लाहौल–स्पीति जिले में फंस गए थे। ऐसी चिन्ताजनक स्थिति में मेरी सरकार ने तुरन्त कार्रवाई करके भारतीय वायु सेना के 7 हेलिकॉप्टरों द्वारा 252 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अतिरिक्त, 2 हज़ार 509 लोगों को रोहतांग सुरंग के सड़क मार्ग से निकाला गया। इस अवधि के दौरान 1

हज़ार 272 छात्रों, शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों को जिला चम्बा के होली तहसील से भी बचाया गया। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र से 120 व्यक्तियों, लगभग 20 हजार भेड़–बकरियों और 350 घोड़ों को भी बचाया गया, जो बेमौसमी बर्फबारी के कारण वहां फंस गए थे। मेरी सरकार इस अभियान को सफल बनाने और फंसे हुए लोगों की जान बचाने में सहयोग प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस सारे अभियान में व्यक्तिगत रूचि दिखाई।

23. मेरी सरकार नशे के सेवन को रोकने के प्रति कृतसंकल्प है। इस दिशा में राज्य स्तर पर बड़ा अभियान आरम्भ किया गया है। वर्ष 2018 के दौरान, स्वापक औषधी एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 1 हज़ार 342 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 10 विदेशी नागरिकों सहित 1 हज़ार 724 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। थाना स्तर पर ड्रग रोकथाम समितियों की स्थापना की गई है। ट्विटर और फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मशहूर हस्तियों के माध्यम से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि नशीली दवाओं के विरूद्ध युवाओं में जागरूकता पैदा की जा सके।

24. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा इस कुरीति को पूर्णतः समाप्त करने के लिए इस अभियान में पड़ोसी राज्यों को शामिल कर इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ व पुलिस महानिदेशकों के स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। इसी उद्देश्य से हिमाचल के मुख्य मंत्री की पहल पर हरियाणा, पंजाब व उत्तराखंड के मुख्य मन्त्रियों तथा राजस्थान, दिल्ली व चण्डीगढ़ के उच्च अधिकारियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन पंचकूला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान खुफिया जानकारी सांझा करने और ड्रग माफिया के विरूद्व संयुक्त रणनीति बनाने तथा इसे लागू करने के लिए एक संयुक्त सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

25. मेरी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 'गुडिया हेल्पलाइन' और 'शक्ति बटन मोबाइल ऐप' शुरू किए हैं। गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2018 से अब तक 1 हज़ार 398 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1 हज़ार 344 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में ईव–टीज़र और अन्य असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए लड़कियों को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए, राज्य की सरकारी पाठशालाओं में छात्राओं को 'आत्म रक्षा' तथा 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 1 हजार 68 स्कूलों में लगभग 54 हजार छात्राओं को राज्य पुलिस द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में जिला सोलन, हमीरपुर और चंबा में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना भी की गई है।

26. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने तथा वन माफिया, खनन माफिया और ड्रग माफिया से कड़ाई से निपटने के लिए 'होशियार सिंह हेल्पलाइन–1090' भी आरम्भ की गई है। कोई भी व्यक्ति इस 'टोल फ्री' नम्बर पर अवैध वन कटान, नशा अथवा खनन गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। इस हेल्पलाइन पर जनवरी, 2018 से अब तक 1 हज़ार 325 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन सभी पर त्वरित कार्रवाई की गई है।

27. मेरी सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। खनिज उत्पादों के अवैध खनन को रोकने तथा आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न नदी–नालों में रेत, बजरी व पत्थर की 121 खानों को खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया गया है। इससे रॉयलटी के रूप में 405 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होगी।

28. मेरी सरकार ने सड़कों के निर्माण व रख–रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश सरकार के प्रयत्नों से भारत सरकार ने मार्च, 2018 तक 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अन्तर्गत 120 सड़कों और 4 पुलों के निर्माण के लिए 385 करोड़ रूपये तथा दिसम्बर, 2018 तक 219 सड़कों और 9 पुलों के निर्माण के लिए 843 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के लिए 1 हज़ार 359 विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों के लिए 3 हज़ार 676 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। नवम्बर, 2018 तक 948 परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया है।

29. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 (नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग–3) हमीरपुर से मण्डी के भाग जिसकी लम्बाई 124 कि0मी0 है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 72बी (नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग–707) पाँवटा साहिब से गुम्मा के भाग जिसकी लम्बाई 97 कि0मी0 है, के डबल लेन उन्नयन के लिए 3 हज़ार करोड़ रूपए का प्राक्कलन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया है।

30. मेरी सरकार 'जल ही जीवन है' के सिद्धान्त को आधार बनाते हुए, प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 500 बस्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर की दर से पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। नवम्बर, 2018 तक 289 बस्तियों को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

31. प्रतिकूल मौसम के कारण गत वर्ष गर्मियों में आए पेयजल संकट का मेरी सरकार ने कुशल प्रबन्धन से सफलतापूर्वक निदान किया। विशेषकर शिमला शहर में स्थिति अधिक गम्भीर होने के कारण, सरकार द्वारा दो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनमें चाबा नामक स्थान से सतलुज नदी से 10 एम0एल0डी0 अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला पेयजल आपूर्ति योजना के गिरी

स्रोत में जल की स्थिरता बनाए रखने के लिए बांध निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सूखाग्रस्त एवं पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1 हजार 594 अतिरिक्त हैण्डपम्पों की स्थापना की गई है।

32. विश्व बैंक ने दिनांक 16 जनवरी, 2019 को 986 करोड़ रूपये की शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की और पहली किश्त के रूप में 292 करोड़ रूपये जारी करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड ने पानी के रिसाव को रोकने के लिए 14 किलोमीटर की मुख्य जलापूर्ति लाईन को बदल दिया है जिससे शिमला में पानी की आपूर्ति 40 एम0एल0डी0 से बढ़कर 51 एम0एल0डी0 हो गई है। इस प्रक्रिया में पानी का रिसाव 27 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से कम रह गया है। क्रैगनैनों से ढली तक 7.5 किलोमीटर, अश्वनी खड्ड से कसुम्पटी तक 4.5 किलोमीटर और संजौली से रिज भण्डारण टैंक तक 2 किलोमीटर लम्बी मुख्य जलापूर्ति लाईनों को बदल दिया गया है।

33. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत नवम्बर, 2018 तक 1 हज़ार 880 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मध्यम सिंचाई परियोजना नादौन के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने हेतु 42 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। जिससे इस योजना के दायें तट के कार्य को जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

34. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक 1 हज़ार 765 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जोकि उपरोक्त वित्त वर्ष के लिए तय किए गए लक्ष्य का 91 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष में विभिन्न उपभोक्ता परिसरों में 20 हज़ार 520 पुराने विद्युत मीटरों के स्थान पर नए इलैक्ट्रोनिक मीटर तथा विभिन्न एच0टी0 व एल0टी0 लाईनों में मौजूद लकड़ी के 4 हज़ार 325 पुराने खम्भों के स्थान पर नए लोहे के खम्भें लगाए गए हैं।

35. मेरी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 873 किलोवाट उच्च क्षमता के ग्रिड संचालित रूफ टॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इसे और अधिक गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत या 4 हज़ार रूपये प्रति किलोवाट राज्य अनुदान घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त 139 किलोवाट उच्च क्षमता के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र, 5 हज़ार 953 सौर स्ट्रीट लाइटें, 5 हज़ार लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयंत्र तथा 3.50 मैगावाट क्षमता की एक लघु जल विद्युत परियोजना प्रदेश में स्थापित की हैं।

36. चालू वित्त वर्ष के दौरान कालका–शिमला रेल लाईन पर भारत सरकार द्वारा पारदर्शी कोचिज़ (विस्टाडोम) चलाई गई है। इससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तथा प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसके अतिरिक्त नंगल डैम–तलवाड़ा रेल लाईन का निर्माण कार्य अम्ब इन्दौरा से दौलतपुर चौक तक पूर्ण कर यातायात के लिए जनवरी, 2019 में खोल दिया गया है। इस रेल लाईन को दौलतपुर चौक तक बढ़ाने से पर्यटकों को चिन्तपूर्णी, ज्वालाजी एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुँचने में सुविधा होगी।

37. भानुपली – बिलासपुर – बेरी रेल लाईन के 20 किलोमीटर के प्रथम चरण के लिए मेरी सरकार ने सम्पूर्ण 25.21 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा शेष भू–अर्जन कार्य प्रगति पर है। नंगल डैम–तलवाड़ा रेल लाईन के लिए राज्य में पड़ने वाली भूमि को अर्जित किया जा चुका है और अब इस भूमि को रेलवे के नाम हस्तान्तरण हेतु रजिस्ट्री एवं इन्तकाल का कार्य प्रगति पर है।

38 राज्य में तीव्र तथा संतुलित औद्योगिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत मेरी सरकार के कार्यकाल में 113 परियोजनाओं को 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस और मानिटरिंग अथॉरिटी' द्वारा मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में 3 हज़ार 622 करोड़ का निवेश होगा और इनमें 7 हज़ार 655 लोगों के लिए रोज़गार सृजन का अनुमान है।

39. मेरी सरकार ने ऑनलाईन मॉनीटरिंग सिस्टम 'हिमप्रगति' प्रारम्भ की है जिसमें बहुउद्देशीय पनबिजली, औद्योगिक, पर्यटन तथा अन्य संरचनात्मक परियोजनाओं के शीघ्र निपटारे एवं अनुमोदन के लिए मुख्य मंत्री द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक 10 हज़ार 202 करोड़ रूपये अनुमानित लागत वाली 79 परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जा रही है।

40. मेरी सरकार ने 'राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन' के तहत 30 उद्यमियों को 10 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोज़गार सृजन के लिए 'मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना' आरम्भ की है। राज्य में 'स्टार्टअप योजना' लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य में 8 केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 40 स्टार्ट–अप पंजीकृत हुए हैं तथा इनमें से 6 स्टार्ट–अप परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश 'स्टार्ट–अप इको सिस्टम' को 'हिल स्टेट लीडर' और 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में मान्यता दी है। भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को स्टार्ट–अप योजना के कार्यान्वयन के लिए 'Regulator Change Champion' का दर्जा दिया गया है।

41. मेरी सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण तथा अनछुए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा युवाओं को स्वरोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'नई राहें, नई मंजिलें' नामक योजना आरम्भ की है। इस योजना के प्रथम चरण में 50 करोड़ रूपये से जंजैहली, जिला मण्डी में ईको टूरिज्म परियोजना, बीड़–बिलिंग, जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग डैस्टिनेशन, चांशल, जिला शिमला में स्की डैस्टिनेशन, लारजी जलाशय, जिला कुल्लू तथा पौंग बांध, जिला कांगड़ा में पर्यटन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में ज़िला शिमला के बनरेडू, संजौली–ढली बाई पास, ज़िला चम्बा के चुवाड़ी व कुन्दी, ज़िला कुल्लू के खोशाला वशिष्ठ, ज़िला मण्ड़ी के कुन्नु, नाचन, ढीम–कटारू व कांगनीधार एवं ज़िला लाहौल–स्पीति के गोम्पा में नये हैलीपोर्ट व हैलीपैड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई–अड्डे की स्थापना के लिए मण्डी के नागचला में स्थान चिन्हित किया गया है।

42. मेरी सरकार द्वारा बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के फलस्वरूप 1 लाख 60 हज़ार पात्र व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। इससे 70 वर्ष से अधिक 60 हज़ार नए व्यक्ति पैंशन के लिए पात्र हुए हैं व 70 वर्ष से 80 वर्ष के बीच 1 लाख व्यक्ति जो कि पहले से पैंशन ले रहे थे, की पैंशन में बढ़ौतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य श्रेणियों के 37 हज़ार 139 पात्र व्यक्तियों को पैंशन प्रदान की जा रही है। चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा 5 लाख 11 हज़ार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने हेतु 600 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा रही है।

43. मेरी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में 'मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना' के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 5 हज़ार रूपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'बेटी है अनमोल योजना' के तहत बी0पी0एल0 परिवारों की लड़कियों के लिए जन्म उपरान्त दिए जाने वाले अनुदान को 10 हज़ार से बढ़ाकर 12 हज़ार रूपये कर दिया गया है। इससे 21 हज़ार 483 लोग लाभान्वित हुए हैं।

44. मेरी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं व किशोरियों के सशक्तिकरण नीति के लिए उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों पर सिफारिश करना, बालिकाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और बालिकाओं व किशोरियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने हेतु सुझाव देना है।

45. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के अन्तर्गत भारत सरकार ने 147 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है। प्रदेश ने 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' को सफलतापूर्वक लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

46. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्गों को गृह निर्माण के अन्तर्गत नए मकान बनाने के लिए 1 लाख 30 हज़ार रुपये प्रति लाभार्थी तथा मकान मुरम्मत के लिए 25 हज़ार रूपये प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान राशि प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 1 हज़ार 412 मकान बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 18 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

47. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत निम्न एवं मध्यम आय वर्गीय परिवारों को नए आवासों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्त वर्ष में 21 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि जारी की गई है तथा 3 हज़ार 158 आवासों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अन्य 777 आवासों का कार्य प्रगति पर है। सितम्बर, 2018 में प्रदेश को इस योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान 42 करोड़ रूपये की लागत से 3 हज़ार 14 आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

48. मेरी सरकार ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, सैनिक विधवाओं, युद्ध विधवाओं, शौर्य पुरस्कार विजेताओं व उनके आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं की बुढ़ापा पैंशन 500 रूपये प्रति माह से बढ़ा कर 3 हज़ार रूपये प्रति माह कर दी गई है। पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को विशेष निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आय सीमा 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये प्रतिवर्ष की गई है। मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 60 वर्ष या अधिक आयु के 1 हजार 682 भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं जो किसी प्रकार की पैन्शन नहीं ले रहे हैं, 934 शौर्य पुरस्कार विजेताओं, युद्ध में शहीद व अपंग हुए सैनिकों के 35 आश्रितों, 54 पात्र नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को 10 करोड़ 55 लाख रूपये की राशि वितरित की है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के राहत एवं पुनर्वास हेतु 60 लाख रूपये की धनराशि वितरित की है।

49. मेरी सरकार ने इस वित्त वर्ष में दालों की खरीद बफर स्टॉक्स के माध्यम से करने का निर्णय लिया है जिसके कारण खर्च में बचत हुई। राशनकार्ड धारकों को विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत 1 किलो दाल चना अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। दालों की खरीद पर पारदर्शिता लाने के कारण फरवरी, 2018 से अक्तूबर, 2018 तक 51 करोड़ 73 लाख रूपये की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त चीनी का क्रय हरियाणा राज्य की सहकारी चीनी मिलों से किया जा रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को माह फरवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक कुल 37 करोड़ 45 लाख रूपये की बचत हुई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने चालू वित्त

वर्ष में दालों एवं चीनी के क्रय पर कुल 89 करोड़ 18 लाख रूपये की बचत की है। इस बचत के कारण सभी राशनकार्ड धारकों के लिए चीनी का मूल्य 5 रूपये प्रति किलो कम किया गया।

50. भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी 'उज्जवला योजना' प्रारम्भ की है जिसमें गृहिणियों को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 86 हज़ार कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मेरी सरकार ने प्रदेश में 'गृहिणी सुविधा योजना' प्रारम्भ की है जिससे प्रदेश की सभी पात्र गृहिणियों को पूर्णतः मुफ्त गैस कनैक्शन जारी किए जा रहे हैं। 31 जनवरी, 2019 तक कुल 40 हज़ार परिवारों को मुफ्त में गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं तथा यह प्रक्रिया तब तक निरन्तर जारी रहेगी, जब तक कि सभी पात्र परिवारों को गैस कनैक्शन नहीं मिल जाते।

51 मेरी सरकार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 567 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रदेश को 43 करोड़ रूपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त 67 करोड़ 70 लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि का अनुमोदन भी प्रदान किया। यह धनराशि भारत सरकार द्वारा आज तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में अनुमोदित की गई अतिरिक्त राशि की तुलना में सबसे अधिक है। प्रदेश में वर्तमान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत केवल एक ही विद्यालय चलाया जा रहा है। मेरी सरकार के प्रस्ताव पर इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार से 3 अतिरिक्त विद्यालय स्थापित करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह विद्यालय जनजातीय क्षेत्र भरमौर, पांगी तथा लाहौल में 52 करोड़ रूपये की राशि से स्थापित किए जाएंगे।

52. तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार पाने के योग्य बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 3 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। मेरी सरकार ने मार्च, 2018 से सितम्बर, 2018 के दौरान आई0टी0आई0 सोलन, नालागढ़, शाहपुर, शमशी, सुन्दरनगर तथा मण्डी में रोज़गार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 127 कम्पनियों ने भाग लिया तथा 4 हज़ार 572 अभ्यार्थियों को रोज़गार के लिए चयनित किया गया।

53. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जिला मण्डी में एक क्लस्टर विश्वविद्यालय विधायी अधिनियम द्वारा स्थापित किया है। सरकार द्वारा प्रदेश में 'अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' नामक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी विद्यार्थियों के नाम विद्यालय के गौरव पट्ट पर अंकित किए जा रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक जीवन में कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हो ताकि वे अपने विद्यालय

के बच्चों को जीवन में दृढ़ता एवं विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश को भारत के अग्रणी मीडिया ग्रुप 'इंडिया टुडे' द्वारा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है।

54. चालू वित्त वर्ष में मेरी सरकार द्वारा सहायक आचार्य (कालेज) के 279 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 120 पद भरे गए। स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 1251 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के 30 हज़ार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जिनमें 12 हज़ार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट स्कूल प्रधानाचार्य के थे, को पूरा करके 2 हज़ार 435 स्कूल प्रधानाचार्य जिन्हें वर्ष 2008 से 2016 के दौरान तदर्थ या प्लेसमेंट आधार पर नियुक्त किया गया था, की पदोन्नति को चालू वित्त वर्ष के दौरान नियमित किया गया जिससे बड़ी संख्या में लम्बित मामलों का निपटारा हुआ।

55. चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य विभाग में 359 चिकित्सकों व अन्य सहित कुल 823 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 746 स्टाफ नर्सों के पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। विभिन्न पैरा मैडिकल स्टाफ के 260 पदों का सृजन किया गया तथा 586 कर्मचारियों को नियमित किया गया।

56. मेरी सरकार प्रदेश में निःशुल्क दवाई नीति के अन्तर्गत जिला अस्पतालों में 330 दवाईयां, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 216, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 106 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 43 दवाईयां मुफ्त प्रदान कर रही है। राज्य के दूर–दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए किलाड़ (पांगी) में अक्तूबर, 2018 में टेलीमेडिसन की सुविधा शुरू की गई है।

57. यह हर्ष का विषय है कि राज्य में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लीनिकों में लाई गई गर्भवती महिलाओं के उच्चतम अनुपात के लिए गैर ई0ए0जी0 राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी सूत्र पर चलते हुए, राज्य ने 'अटल आशीष योजना' के तहत बेबी किट प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, ताकि कोई भी माँ और नवजात शिशु अच्छी देखभाल से वंचित न रहें।

58. मेरी सरकार ने सिविल अस्पताल आनी, थुरल, राजगढ़, तीसा और शाहपुर को 100 बिस्तर वाले अस्पतालों में स्तरोन्नत किया है, 100 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल करसोग को 150 बिस्तर वाले अस्पताल में, 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल नेरवा को 75 बिस्तर वाले अस्पताल में और नागरिक अस्पताल नूरपुर को 200 बिस्तर वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया है। चालू वित्त वर्ष में 4 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है। इन नए खोले गए और स्तरोन्नत किए गए स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 466 पदों का सृजन भी किया गया है।

59. राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को लागू करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। राज्य में 'आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में लगभग 5 लाख परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। शेष जनसंख्या की कवरेज के लिए राज्य में 'हिमकेयर योजना' जोकि 'आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के बराबर है, को प्रारम्भ किया है। इसके अन्तर्गत 2 लाख 75 हज़ार परिवारों को शामिल कर लिया गया है।

60. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों की समस्याओं को दूर करने के लिए शिमला, ऊना, बिलासपुर, पालमपुर, हमीरपुर, चम्बा और पांवटा साहिब में 7 नई डायलेसिस इकाईयां स्थापित की हैं, यह मण्डी, सोलन, कुल्लू और धर्मशाला में मौजूद 4 डायलेसिस इकाईयों के अतिरिक्त है। नाहन और नूरपुर में डायलेसिस इकाईयां शीघ्र ही संचालित की जाएगी।

61. मेरी सरकार ने 24 मार्च, 2018 को 'मुख्य मन्त्री क्षय रोग निवारण योजना' का शुभारम्भ किया है। इस योजना के अन्तर्गत 'क्षय रोग मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़े 2019' का 1 जनवरी, 2019 से 15 जनवरी, 2019 तक 10 जिलों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य टीम द्वारा कुल 364 नए क्षय रोगियों का उपचार किया गया।

62. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में कुल 9 हजार 500 हैक्टेयर भूमि का पौधरोपण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को वन व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 'विद्यार्थी वन मित्र योजना', वनों के प्रबन्धन में स्थानीय लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए 'सामुदायिक वन संवर्द्धन योजना' तथा जंगली जड़ी–बूटियों के संग्रह और निजी जमीन में इसके उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 'वन समृद्धि–जन समृद्धि योजना' आरम्भ की गई है।

63. प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में जिला सिरमौर के तीन विकास खण्डों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत 9 करोड़ 71 लाख की लागत से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य किये गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु 'पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य करने वाले 15 व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु 7 लाख 50 हजार की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

64. मेरी सरकार स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष ध्यान दे रही है तथा इसी क्रम में हाल ही में दो गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के कार्यक्रम को उत्कृष्ट ढंग से चलाने हेतु 20 करोड़ रूपये की राशि बतौर पुरस्कार दी गई है। राज्य ने ग्राम पंचायतों के

लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विकसित की है। राज्य के प्रत्येक जिले में शहरी कस्बों के निकट 8 से 10 पंचायतों का समूह बनाकर कचरा प्रबंधन हेतु एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 12 जिलों की 120 ग्राम पंचायतों को पहले चरण में शामिल किया गया है। कचरा प्रबंधन हेतु इस पहल में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सरकार ने 120–150 पशुओं के लिए 50 घनमीटर क्षमता के 3 बायोगैस प्लॉट ऊना, सोलन तथा कांगड़ा जिलों में स्थापित किए हैं।

65. युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहें हैं। मेरी सरकार द्वारा खेल स्टेडियमों तथा खेल मैदानों के निर्माण के लिए 20 करोड़ 80 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं। 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा खेल मैदान विकसित करने के लिए 6 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि खर्च की जा रही है।

66. चालू वित्त वर्ष में 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के अन्तर्गत 240 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। योजना के अन्तर्गत 730 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण और 116 को रोजगार भी प्रदान किया गया। लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 244 लाभार्थियों तथा 59 स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

67. चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रदेश को कुल 5 हजार 384 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत लोहा, स्टील, सभी प्रकार के यार्न व प्लास्टिक वस्तुओं पर लगने वाले कर में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।

68. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जारी रखते हुए उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2018 से देय 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त जारी की और साथ ही राज्य में कार्यरत अनुबन्ध कर्मचारियों की ग्रेड पे में 25 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने पेंशनरों के हित में अनेक उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार ने श्रेणी–3 और श्रेणी–4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि उनके द्वारा दिनांक 12–06–2018 व इसके पश्चात् समय पूर्व ऐच्छिक सेवानिवृति लेने की दशा में, वे पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में पूर्ण पेंशन (दिनांक 05–07–2018 से) प्रदान की गई है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन पर पेंशन की एवज़ में एक मुश्त राशि प्राप्त की थी।

69. प्रदेश सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों व पैंशनधारकों को 1 जुलाई 2018 से 4 प्रतिशत अन्तरिम राहत की किश्त जारी की है। मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रूपये से बढ़ाकर 225 रूपये तथा पार्ट टाईम वर्कर्ज़ की दिहाड़ी 26 रूपये 25 पैसे से बढ़ाकर 28 रूपये 25 पैसे प्रति घण्टा की गई। राज्य सरकार ने चालकों का स्पेशल भत्ता 800 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया है। वर्ष 2018–19 में कर्मचारियों, पैंशनरों, दिहाड़ीदारों व अन्य कर्मियों को लगभग 1 हजार 417 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए।

70. मेरी सरकार ने वर्ष 2018–19 में कुशल व अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए 5 रोज़गार मेलों और 173 कैम्पस साक्षात्कारों का आयोजन किया जिसके माध्यम से 4 हज़ार 649 नियुक्तियाँ की गई।

71. मेरी सरकार ने एक वर्ष की इस अवधि में ईमानदार प्रयासों के साथ नई–नई योजनाएं आरम्भ की है तथा प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। सभी क्षेत्रों का समान विकास और सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें सबका सहयोग अपेक्षित होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब माननीय सदस्यगण निष्ठा एवं समर्पण से इस प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे और सब मिलजुलकर प्रदेश को प्रगति के शिखर की ओर ले जाने में अपना भरपूर योगदान देंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सब माननीय सदस्यगण इस माननीय सदन में सार्थक चर्चा एवं विचार–विमर्श में बढ़–चढ़ कर भाग लेंगे।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

***

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 04 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 3.30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

04/02/2019/1530/RG/HK/1

अध्यक्ष : इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, विशेष रूप से सदन के नेता, श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री व सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं।

मेरा यह प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का यथासमय अवसर प्रदान किया जाए। वहीं हमारी आपसे प्रार्थना और अपेक्षा भी रहेगी कि नियमों की परिधि में रहकर हम पूरे बजट सत्र के दौरान सकारात्मक चर्चा में भाग लेते हुए सत्र को सफल बनाएं।

शोकोद्गार

अब माननीय मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी व स्वर्गीय श्री शौंकिया राम कश्यप जी, पूर्व सदस्यों, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

04/02/2019/1535/MS/HK/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हालांकि बहुत कम अर्सा रहा है लेकिन इस थोड़े से अर्से में भी इस माननीय सदन के दो पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि श्री जगत सिंह नेगी का 17 दिसम्बर, 2018 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी का जन्म 15 नवम्बर, 1947 को जिला सिरमौर की तहसील शिलाई के कंडियारी गांव में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा राजकीय उच्च पाठशाला शिलाई से उत्तीर्ण की

तथा इंटर की शिक्षा आशा राम इंटर कॉलेज, देहरादून और स्नातक (कला) व कानून की पढ़ाई डी0ए0वी0 कॉलेज देहरादून, उत्तराखण्ड से ग्रहण की। स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी ने वर्ष 1970 में अपना वकालत का कार्य जिला सिरमौर के नाहन से शुरु किया और वर्ष 1973 में खोदरी माजरी जिला सिरमौर में कम्पनी मजदूरों की हड़ताल के समर्थन के कारण जेल गए। इसके बाद वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान लोकदल पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष के पद पर रहे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी वर्ष 1990 में शिलाई विधान सभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्हें सामाजिक कार्यों व गरीब लोगों की सेवा में विशेष रुचि थी। यह सदन स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति तथा उनके परिवार-जनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

इसी तरह से हमारे इसी माननीय सदन के पूर्व में रहे सदस्य, श्री शौंकिया राम जी का निधन 3 फरवरी यानी पिछले कल ही 81 वर्ष की आयु में हुआ है। यह माननीय सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री शौंकिया राम जी का जन्म 14 अक्तूबर, 1937 को जिला शिमला के पुराना जुन्गा में हुआ था। उन्होंने प्रभाकर तक शिक्षा ग्रहण की थी। वे वर्ष 1957 से 1961 तक चौरी बहुउद्देश्यीय सहकारी सभा में सचिव पद पर कार्यरत्त रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित में वर्ष 1962 से 1965 तक प्राप्ति पर्यवेक्षक तथा इसी बैंक में वर्ष 1965 से 1972 तक आलेख व लेखन सामग्री लिपिक के रूप में सेवाएं दीं।

04.02.2019/1540/जेएस/वाईके/1

स्वर्गीय श्री शौंकिया राम जी पहली बार वर्ष 1972 में कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे पुनः मार्च 1985 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए । माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी सहकारिता आंदोलन, ग्रामोत्थान तथा हरिजन कल्याण में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन श्री शौंकिया राम जी के प्रदेश तथा समाज के लिए किए गए कार्यों तथा सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है । उनके

निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विधान सभा के दो पूर्व सदस्यों श्री जगत सिंह नेगी जी और श्री शौंकिया राम कश्यप जी के शोकोद्गार यहां पर प्रस्तुत किए, मैं भी अपने आपको और अपने दल को उसमें शामिल करता हूं । शौंकिया राम कश्यप जी का आज ही संस्कार किया जा रहा है। सदन की व्यस्तताओं की वजह से काफी सदस्य उसमें हिस्सा नहीं ले पाए। उनकी 81 साल की आयु हो गई थी और वे मधुमेह से पीड़ित थे। उन्होंने 10 साल तक इस माननीय सदन में अपनी सेवाएं दी । वर्ष 1972 में वे पहली बार विधायक बनें और वर्ष 1985 में दोबारा विधायक बनें। वे बहुत ही सादगी भरे इंसान थे। साधारण व्यक्तिव के मालिक थे और हर घर में उनकी उपस्थिति थी। वर्ष 1966 के आस-पास वे कांग्रेस में शामिल हुए। जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया कि वे सहकारी बैंक में अपनी सेवाएं देते रहे और उससे जुड़े रहे । अंतिम समय तक वे साधारण व्यक्ति की तरह आम लोगों से मिलते-जुलते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे लेकिन हम उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र, जो उनका कार्य क्षेत्र रहा, उसमें उनके योगदान को हमेशा याद करते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्री जगत सिंह नेगी जी वर्ष 1990 में विधायक बनें। उस समय सरकार बीच में चली गई थी लेकिन अल्पावधि के लिए वे इस माननीय सदन के सदस्य रहें। वे ऐसे चुनाव क्षेत्र से आए जहां पर कांग्रेस का बहुत दबदबा था। लम्बे अर्से तक माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी के पिताजी उस चुनाव क्षेत्र को रिप्रज़ैंट करते रहे और वहां से जगत सिंह नेगी जी जीत कर आए। मैंने बतौर पत्रकार उनके कार्यों को देखा। खासतौर से विधान सभा की एक कमेटी में मेरा उनसे आमना-सामना हुआ। वे बहुत दमदार व्यक्ति थे। वे कानून के ज्ञाता थे और कानून को अच्छी तरह से जानते थे। वे भी आज हमारे बीच नहीं रहे। वे लम्बे समय से बीमार थे। ये दोनों माननीय सदस्य, जिन्होंने इस माननीय विधान सभा को सुशोभित किया, आज हमारे बीच में नहीं हैं।

हम उनकी सेवाओं को याद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

04-02-2019/1545/SS-YK/1

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दो पूर्व सदस्यों, आदरणीय श्री शौंकिया राम जी व श्री जगत सिंह नेगी जी के निधन पर इस माननीय सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किये हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं।

श्री जगत सिंह नेगी जी एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं और आपके जिला से संबंध रखते हैं। किसी समय सिरमौर जिला में कांग्रेस के विरोध में विपक्ष की आवाज़ के रूप में श्री जगत सिंह नेगी जी को जाना जाता था। हालांकि जिस चुनाव क्षेत्र से वे जीतकर आए, उस पर माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी के परिवार का दबदबा रहा है। इनके पीताश्री उस कांस्टीचुऐंसी को रिप्रैजेंट करते रहे लेकिन जब 1990 में देश में जनता दल बना तो वे जनता दल के सदस्य के रूप में चुनकर आए। वे पेशे से वकील थे और मजदूरों के बहुत बड़े हिमायती थे। उनके आंदोलनों में उनकी अग्रणी भूमिका रहती थी। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि खोदरी-माजरी का एक बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित मामला उस समय पूरे प्रदेश में चर्चा में रहा। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें बहुत ज्यादा तशद्दुद भी हुआ। उस आंदोलन में श्री जगत सिंह नेगी और श्री ईश्वर चंद गुप्ता भागीदार थे। इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनकी बुलन्द आवाज़ को कभी कोई दबा नहीं सका। उस पर वे आगे बढ़ते रहे। इसी के कारण 1990 में जनता दल के सदस्य के रूप में वे इस सदन में चुन कर आए। अगर हम इस सदन का रिकॉर्ड भी उस समय का देखेंगे तो जिस प्रकार के उनके क्रांतिकारी विचार इस विषय पर हुआ करते थे और बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी बात को सदन में और सदन के बाहर भी रखते थे। उनकी इच्छा शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज से 10-12 वर्ष पूर्व उनकी किडनी फेल हो गई थी और उनकी पत्नी ने ही उनको किडनी डोनेट कर रखी थी। उस एक किडनी के बल पर ही वे पिछले 10-12 साल से लगातार जीवन-यापन करते रहे

हैं। 2007-2008 में उनकी किडनी की ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था। उनका बहुत क्रांतिकारी कार्यकाल रहा है। जब हिन्दुस्तान में आपातकाल लगा था, जब सारे देश को जेल में बदल दिया गया था, संविधान का गला घोंट दिया गया था, प्रेस बंद हो गई थी, ऐसे समय में भी उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन के कारण वे 19 महीने जेल में MISA के अन्तर्गत बंद रहे थे। उनका निधन प्रदेश के लिए बहुत क्षति पहुंचाने वाला है। उनके दो पुत्र हैं।

इसके अतिरिक्त आदरणीय शौंकिया राम जी एक बहुत ही छोटे स्तर से निकले हुए व्यक्ति थे, लेकिन वे शिमला के मालरोड का एक जाना-माना चेहरा हुआ करते थे। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब वे कॉपरेटिव बैंक में नौकरी किया करते थे। उस वक्त वे एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में सारे कॉपरेटिव बैंक में जाने जाते थे और सहकारिता में उनकी बहुत रुचि भी थी। इसलिए विभिन्न संस्थाओं में जैसे हमारा लैंड मॉर्गेज बैंक था, उसमें भी वे रहे। कॉपरेटिव बैंक के निदेशक मण्डल में भी वे अनेकों वर्षों तक रहे हैं और हमारे साथ लगते क्षेत्र कसुम्पटी से दो बार 1972 और 1985 में भी विधायक रहे हैं। उनका निधन तो कल ही हुआ है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उनके बड़े पुत्र हमारे शिक्षा विभाग में प्रिंसीपल थे और वे बाद में प्रॅमोट होकर असिस्टैंट डायरेक्टर भी रहे हैं तथा अब रिटायर हो चुके हैं। मैं दोनों, जो हमारे भूतपूर्व सदस्य रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।

04-02-2019/1550 /KS/AG/1

अध्यक्षः श्री हर्षवर्धन चौहान जी।

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर माननीय दो पूर्व सदस्यों श्री जगत सिंह नेगी जी और श्री शौंकिया राम जी के बारे में कंडोलैंस रेज़ोलूशन मूव किया है, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं।

जगत सिंह नेगी जी वर्ष 1990 से 1992 तक शिलाई से विधायक रहे हैं। शिलाई चुनाव क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अभी मुझसे पूर्व मुख्य मंत्री जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। वे पेशे से वकील थे और बहुत ही दमदार स्वभाव के थे। जो उन्होने बोलना है, करना है, वे बोलते भी थे ओर करते भी थे, उसका जो मर्जी परिणाम हो, वे कर देते थे। वे कोई प्रोफेशनल लॉयर नहीं थे और वकालत उन्होंने केवल पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं की थी। उन्होंने समाज सेवा के रूप में वकालत शुरू की। हमने देखा है कि उनके जो क्लाइंट होते थे, कई बार उनके पास पैसे भी नहीं होते थे तो वे उनसे पैसे नहीं लेते थे। कई बार तो यह स्थिति होती थी कि वे अपनी जेब से पैसे दिया करते थे। उस समय नाहन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, अब तो कई जगह हो गया है । श्री जगत सिंह नेगी जी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के इन्सान थे। जहां भी वे बैठते थे, मज़ाक करते थे, गप-शप मारते थे। जैसा भारद्वाज जी ने कहा, वे शुगर की बीमारी से पीड़ित थे और वर्ष 2007 में उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और सर गंगाराम अस्पताल में उनकी पत्नी ने अपनी एक किडनी उनको दी । फिर वे वर्ष 2007 से सक्रिय राजनीति से दूर हो गए । वे पांवटा में रहते थे । समाज के प्रति उनका योगदान पावंटा के लिए भी रहा करता था। मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करुंगा कि उनके कंडियारी गांव में, जहां वे पैदा हुए थे, वहां पर एक सीनियर सैकंडरी स्कूल है। उसको आज से आठ-दस साल पहले से मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है मगर उसका काम बहुत धीमी गति से चला हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आप उस मॉडल स्कूल को कम्पलीट करके चालू करें और अगर सम्भव हो तो उसको स्वर्गीय जगत सिंह नेगी जी के नाम से करेंगे तो यह एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और उनकी समाज के प्रति जो सेवाएं हैं, उनको एक श्रद्धाजंलि भी होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भगवान से उनके परिवार को इस दुखद घटना को सहन करने की प्रार्थना करता हूं और यह भी प्रार्थना करता हूं कि वे जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष जी, शौंकिया राम जी कसुम्पटी से दो बार विधायक रहे हैं। उनसे भी सचिवालय में और मालरोड़ पर मिलना-जुलना होता रहता था। वे अक्सर शाम के समय मालरोड़ पर घूमने के लिए आया करते थे। उनसे भी हमारा अच्छा परिचय था। वे समाज सेवक थे और ईमानदार थे । कसुम्पटी चुनाव क्षेत्र के लिए उनका भी अहम योगदान रहा है। मैं दोनों माननीय पूर्व सदस्यों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं । उनके परिवारों को इस सदमे को सहन करने की भगवान शक्ति दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंडोलैंस रेज़ोलूशन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस हाउस में पेश किया, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। जहां तक जगत सिंह नेगी जी का प्रश्न है, वे एक फाइटर थे। कई दफा ज़िदगी में आप बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं लेकिन अगर उनकी पूरी ज़िंदगी देखें तो मेरे लिए तो उनकी ज़िंदगी एक सीख है। मैं पर्सनली उनसे असोसिएट रहा हूं। जिस आंदोलन का ज़िक्र माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने सदन में किया, मैं समझता हूं जगत सिंह नेगी और खोदरी माज़री एक सिनॉनिमस हो गया था।

4.2.2019/1555/av/ag/1

पटेल कम्पनी जो उस समय खुदरो-मादरी प्रोजैक्ट का निर्माण कर रही थी वहां पर एक बहुत दमनकारी किस्म से मज़दूरों का कत्ल कर दिया गया था। इस आन्दोलन को जैसे नैक्सेलाइट का दर्जा दे दिया गया था। सही कहा, ये जेल में चले गये थे; उस समय आई0सी0 गुप्ता जी और श्यामा शर्मा जी भी थीं। बाद में बहुत मुश्किल से जो उन पर नक्सलवाद की छाप लगा दी गई थी उसके लिए मुझे याद है उस समय श्री तुलसी राम जी जो एम0एल0ए0 थे; उनको बिठाया गया था। लेकिन आज विषय यह नहीं है, आज विषय यह है कि हमारे सदन से एक एक्स एम0एल0ए0 जो पूरी जिन्दगी जूझे और अन्त में बीमारी से जूझ नहीं पाये, मैं उनके सम्मान के प्रति अपना सिर झुकाता हूं। मैं यह भी आशा

करता हूं कि जगत सिंह नेगी जी जैसे लोग और पैदा हों तथा इस सदन में आएं। वे मज़दूरों और समाज के शोषित वर्ग के लिए लड़े हालांकि वे अपने आप एक रूलिंग क्लास फैमिली से थे लेकिन उनका नजरिया गरीब के प्रति था। I express my heartfelt condolences to him and to the entire family members.

शौंकिया राम जी बिल्कुल जैसे सुरेश भारद्वाज जी ने कहा वे वैसे ही चेहरे थे जो अपने आप में कसरत करते थे और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वे एक दलित परिवार से सम्बन्ध रखने वाले थे। श्री शौंकिया राम जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सदन में दो बार आया बाकी तो उन्हें मौका नहीं मिल पाया। उनकी यादगार में भी मैं अपना शोक रखता हूं और उनके परिवार को मैं संवेदनाएं देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी को भी जिन्होंने अपना एक पुराना साथी खोया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री अनिरुद्ध सिंह जी ।

श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कन्डोलैंस रैजोल्युशन माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदरणीय शौंकिया राम जी और श्री जगत सिंह नेगी जी के लिए पेश किया है उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

मैं शौंकिया राम जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि वे कसुम्पटी से दो बार विधायक रहें। उनका जन्म 14 अक्तबूर, 1937 को हुआ था और निधन 2 फरवरी, 2019 की रात को हुआ। पिछले कल, सन्डे को उनका शरीर विलीन किया गया। मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि श्री शौंकिया राम जी ने जीवन भर एक ईमानदारी का परिचय दिया। वे हमसे बहुत सीनियर थे लेकिन कभी भी गाड़ी में ट्रैवल नहीं करते थे। वे पुरानी जुन्गा में पैदा हुए और हमेशा बस में आते थे। उनका सबसे बहुत ज्यादा मेल-जोल था तथा वे कसुम्पटी की

एक शान थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और यह भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं।

इसके अतिरिक्त, आदरणीय जगत सिंह नेगी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को भी संवेदनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद।

04/02/2019/1600/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

अध्यक्ष : आदरणीय सुख राम जी।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जिन दो माननीय सदस्यों के बारे में शोकोद्गार प्रस्तुत किए है, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी शिलाई विधान सभा क्षेत्र से विधायक रहे और पांवटा में उनका निवास स्थान था। वे एक स्पष्ट वक्ता के लिए जाने जाते थे। खोदरी-माज़री में हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर पटेल कंपनी के साथ जो विवाद हुआ था, उसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी। स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने उसमें एक सक्रिय आंदोलनकर्त्ता के रूप में भाग लिया था और उसके कारण वह जेल में भी रहे। वे नाहन में व़कालत करते थे और वे मजदूरों के बहुत हमदर्द थे। उनकी खासियत थी कि वे जो डिसिज़न ले लेते थे, उससे जितना मर्जी नुकसान हो जाए उससे पीछे नहीं हटते थे और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए। परन्तु वे कभी भी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते थे। वे अक्सर गरीबों की मदद करते थे। वे जिस भी सभा में बैठते थे, वहां वे अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते थे। वर्ष 2007 में उनकी किडनी फेल हो गई थी और उनकी धर्मपत्नी से उनको एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई। इस हालत में भी उन्होंने एक बहुत जुझारू जीवन-यापन किया। वे कभी यह महसूस नहीं होने देते थे कि वे इतनी गम्भीर

बीमारी से ग्रस्त है। उनके दो पुत्र हैं। मैं उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं।

स्वर्गीय श्री शौंकिया राम जी भी दो बार विधान सभा के सदस्य रहे। वे अपनी ईमानदारी के लिए इस विधान सभा में जाने जाते हैं। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से उनके परिवार-जनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के दो पूर्व माननीय सदस्यों के निधन के ऊपर शोकोद्गार प्रस्तुत किए हैं। सदन के नेता, प्रतिपक्ष व अन्य माननीय सदस्यों ने जहां इसमें अपने उद्गार दिए हैं, मैं भी इसमें अपने-आपको इसमें सम्मिलित करता हूं। स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी, जिला सिरमौर जहां से मैं वर्तमान में विधायक हूं, वहां एक जुझारू नेतृत्व के रूप में जाने जाते रहे हैं। नाहन की बार एसोसिएशन आज भी उनको एक बेहतरीन एडवोकेट, समाज सेवक और राजनीतिज्ञ के रूप में जानती है। उनके निधन के समय, मैं उनके दाह संस्कार पर व्यक्तिगत रूप से गया था। उनका दाह संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ।

स्वर्गीय श्री शौंकिया राम जी एक बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी रहे और हिमाचल प्रदेश के लिए उनका विशिष्ट योगदान रहा। दोनों पूर्व सदस्यों को यह सदन श्रद्धांजलि देने के लिए कृपया चंद क्षणों के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करें।

(माननीय सदन के सभी सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर चंद क्षणों के लिए मौन रखा गया।)

04-02-2019/1605 /NS/DC /1

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन को इस सप्ताह की शासकीय व कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

सोमवार 04 फरवरी, 2019 (1) शोकोद्गार

(2) शासकीय/विधायी कार्य

(3) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2018-19- प्रस्तुतीकरण।

मंगलवार 05 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/ विधायी कार्य

(2) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2018-19ः

(i) सामान्य चर्चा

(ii) मांगों पर चर्चा एवं मतदान; और

(iii) विनियोग विधेयक - पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

(3) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

बुधवार 06 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/ विधायी कार्य

(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा।

वीरवार 07 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/ विधायी कार्य

04-02-2019/1605 /NS/DC /2

(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा एवं पारण।

शुक्रवार 08 फरवरी, 2019 (1) शासकीय/ विधायी कार्य।

(2) गैर-सरकारी सदस्य दिवस

शनिवार 09 फरवरी, 2019 बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 का प्रस्तुतीकरण।

स्वीकृत विधेयक सभापटल पर

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा, सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें माननीय राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन पर माननीय राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 10);
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन)

अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 1);

3. हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2019(2019 का अधिनियम संख्यांक 2); और

4. हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 3) ।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी, अभी तो बज़ट आना है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने चम्बा जिला के ट्राईबल विधान सभा क्षेत्र भरमौर में लिल्ह कोठी न्यू मॉडल कालेज भवन का शिलान्यास किया। इसके बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का दफ्तर देश का सबसे बड़ा दफ्तर है और प्रधानमंत्री जी से ऐसा शिलान्यास करवाया गया जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किया हुआ है। आज के अमर उजाला और अन्य अखबारों में भी यह खबर लगी है और दोनों पट्टिकाएं साथ-साथ लगी हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की पट्टिका लगी है और दूसरी तरफ माननीय वीरभद्र सिंह और भरमौरी जी की पट्टिका लगी है तथा उस समय श्री हंस राज (वर्तमान माननीय उपाध्यक्ष महोदय) भी वहां पर मौजूद थे।

अध्यक्षः हम किसी अन्य मद में इस पर चर्चा कर लेंगे। आप कल बोलने वाले हैं, तब इस विषय को रखना।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी सिर्फ इतनी सी बात सुन लें। आप प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में कोई भी बड़ा उद्घाटन/शिलान्यास करवा सकते हैं। 6 करोड़ रुपये का एक भवन जिसका पूर्व मुख्य मंत्री जी ने पत्थर रखा है और इसके लिए

आप देश के प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवा रहे हैं तथा ऑनलाइन पत्थर रखवा रहे हैं। यह बड़ा अनैतिक और मर्यादाहीन कार्य है। इसलिए मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं।

<u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2018-19 का प्रस्तुतीकरणः</u>

अध्यक्षः यह चर्चा का विषय नहीं है, प्लीज़।

अब माननीय मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम एवं अन्तिम किस्त को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

04.02.2019/1610/RKS/HK-1

मुख्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम तथा अंतिम किस्त प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह अनुपुरक मांगें कुल 3142 करोड़ 65 लाख रुपये की हैं, जिनमें से 2021 करोड़ 69 लाख रुपये गैर-योजना स्कीमों, 671 करोड़ 26 लाख रुपये योजनागत स्कीमों तथा 449 करोड़ 70 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु प्रावधित किए गए हैं।

गैर योजना व्यय में मुख्यतः 1438 करोड़ 70 लाख रुपये Ways & Means Advance हेतु प्रावधित किए गए हैं। लगभग 144 करोड़ रुपये शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के विद्युत प्रभारों को चुकता करने व भू-अधिग्रहण मुआवज़े की अदायगी, 98 करोड़ 91 लाख रुपये बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ उपदान इत्यादि के लिए, 73 करोड़ 97 लाख रुपये धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यकरण व पार्किंग स्थल विकसित

करने के लिए भूमि अधिग्रहण, 60 करोड़ 96 लाख रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान इत्यादि, 31 करोड़ 16 लाख रुपये विभिन्न सड़कों के निर्माण और न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में मुआवज़े के भुगतान, 29 करोड़ 50 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा कल्याण, 18 करोड़ 98 लाख रुपये विधान सभा चुनावों के लंबित दायित्व और आगामी लोक सभा चुनावों पर अग्रिम व्यय, 17 करोड़ 40 लाख रुपये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय और 15 करोड़ 23 लाख रुपये जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत जलाशय के निर्माण और मुआवज़े की अदायगी के लिए प्रावधित किए गए हैं।

योजना स्कीमों के अंतर्गत मुख्यतः 226 करोड़ रुपये HPPTCL के लिए और शिमला शहर में सरकारी भवनों/संस्थाओं की छतों पर ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु, 110 करोड़ 55 लाख रुपये शहरी तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने और विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं के पम्पों को

बदलने इत्यादि के लिए, 101 करोड़ 49 लाख रुपये का भवनों तथा सड़कों के निर्माण हेतु प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 46 करोड़ 04 लाख रुपये कौशल विकास निगम तथा बहुतकनीकी संस्थानों हेतु मशीनरी क्रय करने, 33 करोड़ 66 लाख रुपये AIIMS बिलासपुर के भवन निर्माण के लिए और IGMC शिमला के चमयाणा में Phase-III सुपर स्पैशियलिटी ब्लॉक और मैडिकल कॉलेज, टांडा में छात्रावास के निर्माण, 29 करोड़ 98 लाख रुपये एशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित पर्यटन परियोजना के अंतर्गत होने वाले व्यय वह जिला मण्डी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अंतराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, 26 करोड़ 70 लाख रुपये जनजातीय विकास विभाग के मुख्य निर्माण कार्यों, 25 करोड़ 53 लाख रुपये विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों, राज्य पुस्तकालय के भवन निर्माण व केन्द्रीय विश्वविद्यालय के हरित आवरण, 22 करोड़ 21 लाख रुपये विकेन्द्रीकृत नियोजन व विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों, 17 करोड़ 59 लाख रुपये बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी के दायित्वों को पूरा करने

और 12 करोड़ 27 लाख रुपये न्यायिक अकादमी घण्डल में निर्माण कार्यों और नए न्यायालय परिसर अंब, जिला ऊना के निर्माण इत्यादि के लिए प्राविधित किए गए हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित हैं। 91 करोड़ 94 लाख रुपये बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, 84 करोड़ 13 लाख रुपये "राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि" के अंतर्गत विभिन्न राहत कार्यों हेतु, 50 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क निधि, 48 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 39 करोड़ 60 लाख रुपये एकीकृत सहकारी

04.02.2019/1615/बी0एस0/एच0के0-1

विकास परियोजनाओं व सहकारी सभाओं को ऋण 39 करोड़ 17 लाख रुपये नाहन, हमीरपुर, चम्बा और नेर चौक में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण 30 करोड़ 78 लाख रुपये पोषण अभियान 20 करोड़ 55 लाख रुपये राष्ट्रीय पशुधन मिशन 10 करोड़ 20 लाख रुपये सर्व शिक्षा अभियान और 4 करोड़ 92 लाख रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों की रूप रेखा प्रस्तुत की है। मांगों का पूरा विवरण माननीय सदन के मम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से इन अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल ॥

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**

दिनांक 04 फरवरी, 2019 **सचिव।**